(b) What is the total Quantum of Revenue, actually recovered, and what amount is yet to be recovered?

(c) What are the reasons for non-recovery, if there are amount yet to be recovered?

2. Has/have any official's, who have connived/abetted in the above mentioned frauds, have been Convicted/prosecuted till date?

(a) If so, how many of them? And what actions have been taken against them? (details of the same may be provided).

(b) What action has been taken against the erring parties involved in frauds of various schemes till date?

3. With regard to the new EDI System—

(a) Is it true, that after introducing this new system all the post data, including VABAL/QABAL/DEEC cases will not be available, hence destroying the evidence?

(b) What measures have been taken to retrieve and store such data of various Customs Houses having old Sperry System, which is being phased out?

(c) Which Ports/Customs Houses are being provided the new EDI System, and where Old Sperry System shall be further used?

Misuse of Land Acquisition Act

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Madam, my Special Metnion had been pending since 21st July. I am happy that you have called my name.

We have many Acts on the statute and most of them are obsolete. They belong to the colonial past. One of them is the Land Acquisition Act of 1894. It was enacted by the Britishers for acquiring land forcibly from the Indians because it was an alien regime. This Act is still on the statute in the same form. It is being misused day-in-and-day-out. Though this is a Central Act, it also empowers the State Governments. The appropriate Government here is the State Government and the Central Government. It is being misued for extortion because the politicians and the Ministers want to usurp prime land belonging to private parties. In case the land is not surrendered to them or to their cronies or to real estate touts, who are often their relations and most probably their sons, they are threatened that their land will be acquired. They have to sell it because if you acquire land you pay Rs. 100 or Rs. 180 and the market price of the land is in thousands and thousands of rupees. So, this is used as an instrument of blackmailing and extortion. So, I want the hon. Minister to bring it to the notice of the Government. This old and obsolete Land Acquistion Act should be amended and a new Bill should be brought before the Parliament for enactment.

Now, under clause 3, powers have been given to the Collector or the Deputy Collector, who are employees under the Government. They are bureaucrats. The Government should appoint a tribunal which is headed by a judge so that justice is meted out properly. I have taken interest in raising this matter because there is a multi-crore mega scam in my State. Now, there are 55 clauses in this Act. But there is no provision which says that in lieu of the land acquired. Government land should be given. The Government has to pay compensation or an amount, but not the market price. Then you go to the court and you dispute and get into litigation. There is no provision. But there is clause 55, the last clause, which says:

> "The appropriate Government shall have power to make rules consistent with this Act for the guidance of the officer in this matter".

That means giving directions to the Collector or the Deputy Collector or the Commissioner about the procedure that is to be followed. No structure of this Act can be changed. Now, certain unscrupulous elements went and

exchanged land. They propose to acquire then land which has already been a public land for almost hundred years. It is used by people at Altino Panjim as a playground. Bright ideas came to certain people, including a son of a politician, who got involved in this land scame, which is to the tune of fifteen to twenty crores of rupees. The land which has been acquired in lieu of that, was costing Rs. 180 per Sq. Metre. They have escalated it to may be Rs. 200. And the price of the prime land at Dono Paolo at Taligaon is about Rs. 10,000 per Sq. Metre to Rs. 15,000 per Sq. Metre. The total land which is sought to be acquired by the Government for the jogging park is 29,000 Sq. Metres. Three parties are being favoured. The other eight parties have already been given the compensation. These three parties—Shrimati Jaishri, R.K. Dabolkar, Shrimati Pramila Gurudas Timblow—are being given 15,000 Sq. Metres of land worth about fifteen to twenty crores of rupees. So, it is totally illegal. I request the Central Government to see—for this Act the appropriate Government should be the Central Government—that this Act is not misued blatantly by bringing in some subordinate legislation under clause 55 of the Act. I would like to have somV response from the Government that this draconian, colonial law is properly amended and a new law is brought by

Madam, such a big scam is there and I think it would be appropriate for the Central Government to order CBI inquiry bacause the Government in Goa has already restored powers withdrawn by the Government under the State for the CBI. So, I think it should be sent to the CBI because it is a Central Act which has been misused by the State Government. I request he hon. Minister to see that this Act is amended immediately and the powers of the State tins Parliament by giving powers to a tribunal or to a judge and not to Government bureaucracts who are under the command of politicians.

Government are withdrawan and the powers to have legislative delegation under clause 55 should vest with the Central Government. Thank you. Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Pradhan, would you also like to associate yourself with it?

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : धन्यवाद महोदया, मैं इस विषय से स्वय को संबद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है क्योंकि में थाना म्युनिसिपैलिटी का प्रैजीडेट था और इस सबंधं मे मेरा काफी अनुभव है । इसलिए मैं इस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं । लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट बहुत पुराना हो गया है और अब उसमें काफी संशोधन करने की आवश्यकता है , सुधार करने की आवश्यकता है । उसमें दो किस्म की आपत्ति आती है । लैंड ऐक्वीजिशन करने के लिए जब हम जाते हैं तो जो कम्पनसेशन तय किया जाता है, उस कम्पनसेशना के बारे में नये नॉर्म्स तय करने की आवश्यकता है, अब पुराने सब आउटडेटिड हो गये हैं । इसके अतिरिक्त जो आदमी आपको लैंड देना चाहता है । उसके लिए भी कुछ आल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है । जैसे मैं बताना चाहता हूं कि हम रोड वाइडनिंग के लिए जगह लेते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक मिनट में आपको असोसिएट करना था ।

श्री सतीश प्रधान : महोदय, मैं एक मिनट में खत्म करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप एक मिनट से ज्यादा समय ले रहे हैं।

श्री सतीश प्रधान : महोदया, मैं जानता हूं कि सुबह से सब लोग बैठे हैं, मैं किसी को तंग नहीं करना चाहता । जब हम रोड वाइडनिंग करना चाहते हैं तो किसी का घर ले लेते है, पर उस समय उस घर के मालिक को उधर से उठकर बहुत दूर जाना पड़ता है । गांव बड़ा हो जाता है लेकिन उसका घर स्थर से हटेगा तो उसको गांव छोड़कर बाहर जाना पडता है । यह जो आपत्ति आती है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता था ।

श्री खान गुफान जाहिदी (उत्तर प्रदेश) : महोदया,मैं भी इनसे अपने आपको असोसिएट करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं । लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट

के बारे में हमारे ऑनरेबल साथी जॉन फर्नाडिस साहब ने अपनी बात रखी है। सच यह है कि प्राइम लैड जो काश्त में इस्तेमाल होती है, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग की सारी जो लैंड डैवलपमेंट अथॉरिटी है, पी0डब्ल्यू0डी0 है, इरीगेशन है, स्टेट्स के कई ऐसे महकमे हैं जो नहर बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए, लिंक रोड बनाने के लिए, और पंचयातघर बनाने के लिए स्कूल बनाने के लिए काश्तकारों से काफी जमीन – हजारों-हजार, एकड़ जमीन लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत, जो अमैंड हुआ है, 1984 में अमैंड भी हुआ और जब कि उसके अदंर यह प्रोवीजन कर दिया गया कि मार्किट रेट दिया जाएगा। यह भी प्रोवीजन कर दिया कि जिस रोज से दिया जाएगा, अगर उसे कम्पनसेशन अदा नहीं हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। लेकिन यह होता नहीं है होता यह है कि कोई भी ऐजेंसी जो मकान बना रही है, इंदिरा आवास बना रही है गांव की सभाओं की जमीन ले ली जाती है । जो हाउसिंग बोर्ड स्कीप्स चलती है बड़ी-बड़ी डैवलपमेंट अथारिटीज की चलती है – हमारे उत्तर प्रदेश के 85 जिले हैं, कम से कम 30 -40 ऐसी डैवलमेंट अथारिटीज बन गयी है, मुरादाबाद बन गयी है, बरेली बन गयी है, गोरखपुर बन गयी है, बहुत सी डैवलपमेट अथारिटी बन गयी है, यह जमीनें लेती है, प्राइम लैंड लेती है- इ काश्तकारों की ओर जो किनारें – किनारे की जमीन है, जो शहर के किनारे की खेतिहर जमीने है जिस पर सब्जियां बोई जाती है, उन जमीनों को ले लेती है। न सिर्फ ले लेते हैं बल्कि उसका कम्पनसेशन भी नहीं देते हैं .....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप सिर्फ एसोसिएट करिएगा। आप इतना लम्बा स्टेटमेंट मत करिए। अभी तो एक स्टेटमेंट और आना है।

श्री खान गुफरान जाहिदी : जब मैंने देखा कि सभी बोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कहूं। मैं आपको इन्फारमेंशन दे रहा हूं। जानकारी दे रहा हूं। मेरा कहना यह है कि किसानों की जमीन ले ली जाती है और उसका इस्तेमाल तीन साल तक नहीं होता है। यह सच बात है। अगर तीन साल तक कोई अथारिटी काम नहीं करती है। और वह किसानों से जमीन लेकर डाल देती है। उस जमीन पर किसान अपनी खेती भी नहीं कर सकता है इसलिए उसका जब तक सही तौर पर प्लान तैयार न हो जाए उस वक्त उस पर खेती करने की इजाजत किसान कोदी जानी चाहिये। उस वक्त तक कोई काम न किए जाए जब तक कि उसका पैसा, कम्पनसेशन अदा न कर दिया जाए। ऐसा भी हुआ है कि मकान बन गए और मकान बनने के बाद जब मकानों का अलाटमेट शुरू हुआ तो किसान बड़ी तादाद में आकर खडे हो गए और उन्होंने मकानों का अलाट नहीं होने दिया और उनका हंगामा काफी दूर तक बढ़ता चला गया .....(**व्यवधान**)

श्री सतीश प्रधान : मैडम, जब हम बात कर रहे थे तो हमें .....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं अगर आपको अलाऊ नहीं करती प्रधान जी तो शायद इनको भी अलाऊ नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको मैंने देखा कि You are an experience person I allowed you Now he also wants to contyribute something

श्री खान गुफरान जाहिदी : मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत से सूबों ने अपने-अपने यहां भी लैंड एक्वीजिशन एक्ट बनाए हैं लेकिन सेन्ट्रल एक्ट उन पर हावी है। बहुत जगह पर जिन्होंने सदर हिन्दुस्तान से अपनी मुहर लगा दी है, वह अपना लैंड एक्वीजियशन एक्ट खुद चला रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना इतना सा है कि उस वक्त तक कोई काम न किया जाए काश्तकारों की जमीन का जब तक कि उनको कम्पनसेशन मय इन्टरेस्ट के न दे दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : थैंक्यू बहुत-बहुत धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

National Social Assistance Programme

The Minister of State of the Ministry of Rural Development (Shri Babagounda Patil): Madam, the National Social Assistance Programme (NSAP) is being implemented since 15th August, 1995. It has three components at present. Under National Old Age Pension Scheme (NOAPS), the Central assistance is given @ Rs. *75/-* per month to destitutes who are aged 65 years or more. Under National Family Benefit Scheme (NFBS), lumpsum benefit is given to households below poverty line on the death of the primary breadwinner. An amount of Rs. S,00(y- is given in case of natural death and Rs. *W,0(Xy-* in case of accidental